(ख) 1992-93 की दौरान उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है । तथापि, 1991-92 के दौरान स्वास्थ्य के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए 5.79 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई थी । वर्ष 1991-92 के दौरान साक्षरता अभियान (आपरेशन ब्लैक बोर्ड) पर अनुमानित खर्च 6.20 करोड़ रुपये था ।

(ग) व (घ) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य को आबंटित धनराशि के इस्तेमाल की स्थिति नीचे दर्शाई गई है ।

(करोड़ रुपयों में)

कार्यक्रम	आबंटन	उपयोग
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	21.32	23.08
2. जवाहर रोजगार योजना	81.89	100.39
3. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	16.33	15.14

इस प्रकार, 191-92 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम को छोड़कर प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निधियों का उपयोग आबंटित राशि से अधिक हुआ है ।

ग्रामीण उद्योग के लिए अपर्याप्त धनराशि

735. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए वर्तमान वर्ष में अपर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं । वर्ष 1992-93 के दौरान इस विभाग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जरिए योजनागत स्कीमों के तहत ग्रामीण उद्योगों के लिए 19100 लाख रु. आबंटित किए गए हैं । 1991-92 के दौरान बजट में इतना ही प्रावधान किया गया था । तथापि, पुनर्विनियोग द्वारा 1991-92 के दौरान बजट में 200 लाख रु. की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी गयी थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ग्रामोद्योग के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को आबंटित की गयी राशि इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (रु. लाखों में)
1989-90	17500
1990-91	18600
1991-92	19300

उत्तर प्रदेश को भूमि सुधारों के लिये विशेष सहायता

736. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश को भूमि सुधारों के लिए विशेष सहायता प्रदान करने पर विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?